

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	ब्योरे	
अ. बैंक के बारे में सामान्य जानकारी			
1	कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838	
2	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	
3	पंजीकृत पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005	
4	वेबसाइट	www.idbi.com	
5	ई-मेल आईडी	idbiequity@idbi.co.in	
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2016-17	
7	क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड-वार)	कोड: 64191- आईडीबीआई बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा नियंत्रित एक बैंकिंग कंपनी है.	
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी निर्माण करती है/ जिन्हें प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)	1. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ट्रेजरी सेवाएं	
9	लोकेशनों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कार्यकलाप किए जाते हैं.	1,896 शाखाएं	
	क. अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या (प्रमुख 5 के ब्योरे दें)	बैंक की एक शाखा डीआईएफसी, दुबई और एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा जीआईएफटी शहर, गुजरात, भारत में है.	
	ख. राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या	1894	
10	बाजार जहां कंपनी अपनी सेवाएं देती है. (स्थानीय/ राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय)	बैंक अपनी उपस्थिति वाले सभी लोकेशनों पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है.	
आ. कंपनी के वित्तीय ब्योरे			
1	चुकता पूंजी (₹ लाख में)	2,05,881.51	
2	कुल कारोबार (₹ लाख में)	31,75,896.60	
3	कर पश्चात कुल लाभ/हानि (₹ लाख में)	(5,15,813.97)	
4	यथा 31 मार्च 2017 को कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ/हानि ₹ 698 करोड़ के घाटे में परिणत हुआ है. तथापि एक तत्पर पहल के रूप में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों पर ₹ 4.35 करोड़ व्यय किया.	
5	उन कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त बिन्दु 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है:		
क्र. सं.	कार्यकलाप	सीएसआर परियोजनाओं की सं.	राशि (₹ लाख)
क.	स्वास्थ्य	6	122.75
ख.	ग्रामीण विकास	2	74.25
ग.	शिक्षा	10	111.04
घ.	सामाजिक-आर्थिक विकास	1	11.75
ड.	पर्यावरण	4	55.27
च.	खेल-कूद संवर्धन	2	59.95
कुल		25	435.01

2016-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उपगत व्यय निम्नानुसार हैं:

स्वास्थ्य

क्र. सं.	कार्यकलाप/संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1.	टाटा मेडिकल सेंटर	निम्न के लिए वित्तीय सहायता i) चरण II विस्तार खंड 6- बेड, ii) 40 वंचित / आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों का उपचार, iii) 25 रोगियों के लिए भर्ती सुविधाओं के साथ प्रशामक चिकित्सा इकाई	100.00
2.	रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड (साइटसेवर्स)	आंखों की देखभाल संबंधी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	13.97
3.	रामकृष्ण मठ	धर्मार्थ औषधालय के लिए एक एक्स-रे मशीन और सहायक डिजिटल सिस्टम की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	6.31
4.	कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय, झारग्राम नगरपालिका	जनजातीय लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	1.49
5.	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	सेनेटरी नैपकिन (डबल सिलेंडर) और इन्सिनेरेटर मशीन के लिए स्वचालित वेडिंग मशीन की स्थापना.	0.73
6.	रेड क्रॉस	गरीब लोगों के लिए भोजन प्रदान करना	0.25
कुल			122.75

ग्रामीण विकास

क्र. सं.	कार्यकलाप/संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1.	उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों में सीएसआर कार्यकलाप	वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले में भभौरा, दो गांवों को विभिन्न सीएसआर कार्यकलाप जैसे सड़क का निर्माण, सामुदायिक हॉल का निर्माण, सौर ऊर्जा लैंप पोस्टों, टॉयलेट और सबमर्सिबल वाटर पंप के प्रावधान तथा स्कूल बिल्डिंग के नवीकरण के लिए गोद लेना.	70.49
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि	आदर्श ग्राम का विकास.	3.76
कुल			74.25

शिक्षा

क्र. सं.	कार्यकलाप/संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1.	राज्य मध्याह्न भोजन कार्यालय को सहयोग	5000 तुला मशीनों की खरीद के लिए राज्य मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यालय को वित्तीय सहायता	44.10
2.	अपंग कल्याण शिक्षण संस्था	स्कूल के लिए क्लासरूम फर्नीचर, सौर प्रणाली और अन्य सामानों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	1.20
3.	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (नेडफ्री)	डिजाइनर मोमबत्तियों और अन्य स्थानीय हैंडीक्राफ्टों की मार्केटिंग हेतु एक शोरूम की स्थापना के लिए और तीन साल तक की इसकी परिचालन लागत में सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता	4.80
4.	उत्तराखंड में पुनर्वास परियोजनाएं (आंगनवाड़ी केंद्र)	पिथौरागढ़ जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित आपदा प्रभावित स्थानों पर पांच आंगनवाड़ी केंद्रों या सहायक नर्स मिडवाइफ केन्द्रों का निर्माण	17.36
5.	मारा टी टी चाको एंड अब्राहम चैरिटेबल ट्रस्ट	मिजोरम के सइहा जिले में मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए अक्षमता अनुकूल विशेष स्कूल के बचे हुए हिस्से का निर्माण कार्य पूर्ण करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	12.00
6.	ऑल इंडिया मूवमेंट (एआईएम) फॉर सेवा	एक वर्ष की अवधि हेतु 46 छात्रों के लिए फ्रीस्टूडेंट होम, लखनऊ को वित्तीय सहायता.	3.45

क्र. सं.	कार्यकलाप/संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
7.	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई)	गुजरात में करनाली ग्राम पंचायत में कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन.	15.13
8.	दृष्टिबाधितों के लिए एनएबी कार्यशाला, महाराष्ट्र	30 स्टेनोग्राफी छात्रों को कोर्स के सफल समापन पर 30 ब्रेल शॉर्टहैंड मशीन तथा एमएस-सीआईटी और अंग्रेजी और मराठी स्टेनोग्राफी कोर्स के लिए एक लेजर प्रिंटर और 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर देने के लिए वित्तीय सहायता	7.69
9.	उपायुक्त (डीसी) ऑफिस सड़हा, मिर्जौरम	सड़हा जिले के स्कूलों में 223 वाटर फिल्टर लगाना	4.46
10.	नवी मुंबई सनराइज सोसाइटी का रोटरी क्लब	10 बच्चों के लिए शिक्षा लागत का प्रायोजन किया जा रहा है	0.85
कुल			111.04

सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण

क्र. सं.	कार्यकलाप/संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1.	हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट	महाराष्ट्र के नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में पानी ले जाने में आसानी के लिए ग्रामीण महिलाओं को वाटर व्हील्स प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	11.75

पर्यावरण

क्र. सं.	कार्यकलाप/संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1.	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी)	‘लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स’ कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसके अंतर्गत चार राज्यों के चुनिन्दा गांवों में 5000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम प्रदान किए गए.	32.02
2.	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एमएसई)	एमएसई कैंपस में ‘सेंटर ऑफ एक्सलेस’ के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने हेतु वित्तीय सहायता	6.25
3.	स्वीकार अकेडमी ऑफ रीहैबिलीटेशन साइसेज	छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने हेतु वित्तीय सहायता	12.00
4.	दिलासा संस्था	चौथे जलसंभर विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय सहायता	5.00
कुल			55.27

खेल-कूद संवर्धन

क्र. सं.	कार्यकलाप/संगठन का नाम	प्रयोजन	राशि (₹ लाख)
1.	युवा कार्य एवं खेलकूद निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	युवा कार्य एवं खेलकूद निदेशालय, त्रिपुरा सरकार को राज्य द्वारा संचालित खेल अकादमी के लिए जिम्नास्टिक्स उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	9.95
2.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	राष्ट्रीय खेल विकास निधि को अंशदान	50.00
कुल			59.95

इ. अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियाँ हैं?	हाँ. बैंक की पाँच देशी सहायक संस्थाएं अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्विरिटीज लि., आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि., आईडीबीआई इंटेक लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. हैं.
----	--	--

2	क्या सहायक कंपनी/ कंपनियाँ मूल कंपनी के कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी(यों) की संख्या सूचित करें.	नहीं
3	क्या अन्य कोई संस्था/ संस्थाएं (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनके साथ कंपनी अपने कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती है? यदि हाँ, तो उस संस्था/ उन संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक].	नहीं

ई. कारोबार दायित्व संबंधी जानकारी

1. कारोबार दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे

क.	कारोबार दायित्व नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों के ब्योरे	
	डीआईएन संख्या	02611496
	नाम	श्री कृष्ण प्रसाद नायर
	पदनाम	उप प्रबंध निदेशक
ख.	कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे	
	डीआईएन संख्या	00064934
	नाम	श्री आलोक सेनगुप्ता
	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक
	टेलिफोन नं.	+91-22-66552300
	ई-मेल आईडी	aloke.sengupta@idbi.co.in

2. सिद्धान्त-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/ नीतियां (हाँ/ नहीं में उत्तर दें)

		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
क.*	क्या आपके पास के लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ख.	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ग.**	क्या यह नीति राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
घ.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ड.	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
च.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ\$	हाँ#
छ.	क्या नीति के बारे में सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ज.	क्या नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
झ.	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों से संबंधित अंशधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/ नीतियों के संबंध में शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ञ.	क्या कंपनी ने इस नीति के बारे में कार्यों का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षण/ मूल्यांकन कराया है?	नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभाग प्रमुख उत्तरदायी हैं. अनुपालन विभाग रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित नीतियों के कार्यान्वयन के अनुपालन की निगरानी करता है..								

नोट:

- * बैंक की विभिन्न नीतियां जिन्हें औपचारिक रूप से कार्यान्वित किया गया है, बैंक के विभिन्न कार्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं।
सिद्धान्त 1 - बैंक मुख्य रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में दिए गए सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।
सिद्धान्त 2 - सिद्धान्त 2 के अंतर्गत दिए गए अधिकतर कार्यकलाप बैंक की ऋण नीति और उत्पाद दिशानिर्देशों से शासित हैं जो कि गोपनीय हैं।
- ** बैंक की नीतियां नियामक और सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं अतः ये राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।
- \$ सीएसआर नीति का लिंक - <http://www.idbi.com/csr-policy.asp>
- # बैंक की पॉलिसियां अर्थात् ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, नागरिक चार्टर और बीसीएसबीआई कोर्ड, ग्राहक शिक्षा के अंतर्गत <http://www.idbi.com/customer-carecentre.asp> लिंक पर जनता को देखने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

2क. यदि किसी भी सिद्धान्त के संबंध में क्र.सं. 2 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया कारण बताएं: (2 विकल्पों तक टिक करें)
(किसी भी सिद्धान्त के लिए नीति न होने के कारण का उल्लेख किया जाए)

क.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है।	पी7 के लिए नीति नहीं होने का कारण:
ख.	कंपनी ऐसे चरण में नहीं है जिसमें वह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति में पाए।	बैंक में पी7 के लिए कोई दस्तावेजीकृत नीति नहीं है। तथापि, यह हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ जिम्मेवारीपूर्वक जुड़ा रहा है। बैंक विकास वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा भारत के वित्तीय ढांचे की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा, बैंक बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, वित्तीय समावेशन आदि के क्षेत्रों में सुधार के लिए नीति निर्माताओं से जुड़ा रहा है।
ग.	कंपनी के पास कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है।	
घ.	यह कार्य अगले 6 माह के भीतर करने की योजना है।	
ड.	यह कार्य अगले 1 वर्ष के भीतर करने की योजना है।	
च.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3 कारोबार दायित्व संबंधी अभिज्ञासन

क.	कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की बारंबारता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक.	बैंक का कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन बोर्ड के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।
ख.	क्या कंपनी कारोबार दायित्व या निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया गया है?	हाँ, बैंक कारोबार दायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कारोबार दायित्व रिपोर्ट www.idbi.com पर देखी जा सकती है। यह रिपोर्ट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में 2015-16 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जा रही है।

उ. सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

1 सिद्धान्त 1 : कारोबार का संचालन और प्रबंधन अपने आप में आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए

क.	क्या आचार नीति, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबन्धित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? हाँ/नहीं.	हाँ, इसमें केवल बैंक शामिल है। बैंक के पास भ्रष्टाचार, अनाचार और निधियों के दुर्विनियोजन की जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था है। बैंक ने सतर्कता संबंधी मामलों के निपटान के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप आंतरिक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की हैं। कर्मचारियों की सुविधा के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सामान्य रूप से सतर्कता मामले के लिए तथा विशिष्ट रूप से बैंकों के लिए जारी अद्यतन परिपत्र/ दिशानिर्देश बैंक के इंटरनेट पर रखे गए हैं। साथ ही, इन दिशानिर्देशों को बैंक के लिए सतर्कता मैनुअल के रूप में संकलित किया गया है जिसे वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। बैंक में निवारक सतर्कता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग के वार्षिक कार्य योजना (एएपी) हरेक वित्तीय वर्ष में तैयार की जाती है जिसमें मुख्यतः निवारक सतर्कता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनाई जानेवाली गतिविधियों का विस्तार से वर्णन रहता है।
----	---	--

ऐसी गतिविधियों का सारांश निम्नानुसार प्रकार है:

- **अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी (एआरएएल):**

- क) एआरएएल की ऑनलाइन प्रस्तुति अनिवार्य कर दी गई है.
- ख) बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत एआरएएल की नमूना जांच करना जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी अधिकारी अर्थात् महाप्रबंधक (ग्रेड ई) एवं उनसे उच्च अधिकारी तथा शेष एआरएएल के 10% शामिल हैं.

- **संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची (एएलएसओ)**

ऐसे अधिकारियों की एक सहमत सूची सीबीआई प्राधिकारियों के परामर्श से वार्षिक रूप से तैयार की जाती है जिनके विरुद्ध उनकी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा के संबंध में शिकायतें, संदेह या शंकाएं हैं.

- **संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची (एलओडीआई)**

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, ईमानदारी पर संदेह वाले अधिकारियों की सूची वार्षिक रूप से तैयार की जाती है तथा उसकी समीक्षा की जाती है.

- **संवेदनशील पदों की पहचान और स्टाफ का आवर्तन**

संवेदनशील पदों की पहचान वार्षिक आधार पर की जाती है तथा इस संबंध में बैंक के विभिन्न वर्टिकलों से मासिक/ तिमाही फीडबैक लेकर बैंक द्वारा ऐसे पदों के बारे में कार्य आवर्तन नीति को लागू किया जाता है.

- **बैंक में संवेदनशील पदों पर स्टाफ आवर्तन की निगरानी की जाती है तथा मासिक / तिमाही रिपोर्टों में इसकी सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को दी जाती है.**

मानव संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि एएलएसओ/ एलओडीआई में शामिल अधिकारियों को संवेदनशील कार्यभार न सौंपे जाएं. इसकी निगरानी सतर्कता विभाग द्वारा की जाती है.

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना**

प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवेदन फॉर्म/प्रपत्र डाउनलोड योग्य फॉर्मेट में बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं. संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों और प्रदान की जानेवाली सूचनाओं की जानकारी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दी गई है तथा यह आवेदन फॉर्म का हिस्सा भी हैं.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक समान कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए रूप में मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) को सक्रिय किया गया है. दी गई निविदाओं/ संविदाओं को मासिक आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है. सुरक्षा में कमियों को दूर करने के लिए फिनेकल प्रणाली में लगातार सुधार किया जाता है. धोखाधड़ियों को नियंत्रित/ रोकने के लिए धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली को एक साधन के रूप में लागू किया गया है.

- सीटीई प्रकार का निरीक्षण**
 सतर्कता विभाग, वेंडर को भुगतान, निविदा और संविदा आदि प्रदान करने जैसी मौजूदा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने/ सुदृढ़ करने के लिए प्रदान की गई संविदाओं का यादृच्छिक आधार पर अध्ययन तथा समीक्षा करता है. ऐसी जांच का उद्देश्य केवल अनाचार का पता लगाना और भ्रष्ट अधिकारी को सतर्कता के दृष्टिकोण से दंडित करना भर नहीं है, बल्कि बैंक की प्रणालियों / प्रक्रियाओं में सुधार में मदद करना भी है ताकि बेहतर तकनीकी और वित्तीय नियंत्रण के साथ-साथ भावी संविदाओं में चूकों/ अनियमितताओं से बचा जा सके.
- चौकसी एवं पता लगाना**
आकस्मिक सतर्कता दौरा (एसवीवी): सभी स्तर के कर्मचारियों में जागरूकता लाने तथा धोखाधड़ी/ दुरुपयोग की घटना को रोकने के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सतर्कता अधिकारियों द्वारा चुनिन्दा शाखाओं का आकस्मिक दौरा(एसवीवी) किया जाता है.
एफटीएनपीए, क्यूएम, ओटीएस/ एनएस मामलों की जांच: पहली बार अनुप्रयोज्य आस्ति खातों (एफटीएनपीए), त्वरित मरणशील (क्यूएम), एकबारीय निपटान मामले (ओटीएस)/ तय निपटान (एनएस) मामलों की जांच आकस्मिक आधार पर की जाती है. इन मामलों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वित्तीय अधिकारों का उपयोग मनमाने तरीके से न किया जाए, बल्कि इनका उपयोग उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाए तथा बैंक में प्रणाली और प्रक्रियाओं की तुलना में वर्तमान कार्यप्रणाली की जांच उन कारकों को हटाने या कम करने के उद्देश्य से किया जाए जो भ्रष्टाचार और अनाचार के लिए मौका प्रदान करती हैं. साथ ही यह पता लगाना कि स्टाफ जवाबदेही है या नहीं.
- निवारक सतर्कता समितियां (पीवीसी)/ अंचल निवारक सतर्कता समितियां (जेडपीवीसी)**
 बैंक का सतर्कता विभाग सुनिश्चित करता है कि सतर्कता से संबन्धित विषयों/मामलों को निपटाने और उन पर विचार-विमर्श के लिए अंचल निवारक सतर्कता समितियों की बैठक सभी ग्यारह अंचलों में तिमाही में एक बार की जाए. इससे सतर्कता को लेकर जारी किए गए अद्यतन दिशानिर्देशों पर चर्चा के अलावा प्रणाली में कमियाँ, यदि कोई है, को दूर करने के लिए संबंधित अंचल में शाखाओं/ प्रोसेसिंग केन्द्रों में धोखाधड़ी/ गलत कार्यप्रणाली को बढ़ावा देनेवाली कमजोर बिन्दुओं/ क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलती है तथा कमजोर क्षेत्रों में निगरानी को कड़ा किया जा सकता है. इन बैठकों में नामित प्रतिनिधि के रूप में सतर्कता विभाग के अधिकारी उपस्थित होते हैं.
- सतर्कता जागरूकता कार्यशालाएं**
 पूरे बैंक में सतर्कता जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं जिनमें बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) उपस्थित रहते हैं. इन कार्यशालाओं में इस बात पर जोर दिया जाता है कि निवारक सतर्कता एक सक्रिय कार्य है जिसमें बैंक में, विशेषकर, धोखाधड़ी, अनाचार, दुर्विनियोजन और भ्रष्टाचार रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि बैंक को वित्तीय या प्रतिष्ठागत हानि से बचाया जा सके और सामान्य रूप में संगठन को मजबूत किया जा सके.

	<ul style="list-style-type: none"> • बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा <ul style="list-style-type: none"> - सभी मामलों में समग्र प्रगति की निगरानी करना तथा एमडी एवं सीईओ के साथ तिमाही आधार पर संरचित बैठक का आयोजन करना तथा ऐसी संरचित बैठकों में उभरने वाले कार्य बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करना. - बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा से संबन्धित मामलों पर तिमाही आधार पर निदेशक मण्डल को ज्ञापन प्रस्तुत करना. • त्वरित दंडात्मक कार्रवाई मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की निगरानी करते हैं. • सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है. स्टाफ सदस्यों/ जनता/ ग्राहकों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए शाखाओं/ कार्यालयों में सप्ताह के दौरान सेमिनार, बैठकें, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती हैं. • सतर्कता संबंधी शिकायतें मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सतर्कता की दृष्टि से प्राप्त शिकायतों की जांच सुनिश्चित करते हैं और जहां जरूरी हो वहां उचित कार्रवाई करते हैं. 								
<p>क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू होती है?</p> <p>ख. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया है? यदि ऐसा है तो करीब 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.</p>	<p>नहीं, यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू नहीं होता है.</p> <p>वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने कुल 58,388 ग्राहक शिकायतों पर कार्रवाई की इनमें से 57,328 शिकायतें 2016-17 में प्राप्त हुईं और 1060 शिकायतें वर्ष 2015-16 की थीं. यथा दिनांक 31 मार्च 2017 तक लगभग 99%, अर्थात् 57,766, शिकायतों का निवारण किया जा चुका था तथा 622 शिकायतें निपटान के लिए लंबित थीं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'शिकायत निवारण नीति' तैयार की है जो शिकायतों के समयबद्ध निवारण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.</p> <p>वर्ष 2016-17 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा 112 शिकायतें प्राप्त की गईं. इन सभी शिकायतों की जांच/छानबीन सतर्कता की दृष्टि से की गई और सीवीओ की सहमति से इनका संतोषजनक समाधान किया गया.</p> <p>शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों का ब्योरो निम्नानुसार है :</p> <table border="1" data-bbox="837 1730 1436 1885"> <thead> <tr> <th>यथा दिनांक 01.04.16 को लंबित</th> <th>2016-17 के दौरान प्राप्त</th> <th>2016-17 के दौरान निवारण</th> <th>यथा दिनांक 31.03.17 लंबित</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1,193</td> <td>1,193</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	यथा दिनांक 01.04.16 को लंबित	2016-17 के दौरान प्राप्त	2016-17 के दौरान निवारण	यथा दिनांक 31.03.17 लंबित	0	1,193	1,193	0
यथा दिनांक 01.04.16 को लंबित	2016-17 के दौरान प्राप्त	2016-17 के दौरान निवारण	यथा दिनांक 31.03.17 लंबित						
0	1,193	1,193	0						

2 सिद्धान्त 2 : कारोबार द्वारा ऐसी उत्पाद और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो विश्वसनीय हों और अपने सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हों

<p>क. 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिनको तैयार करने में सामाजिक या पर्यावरण सरोकार, जोखिम और/या अवसरों का ध्यान रखा गया है.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए): बेसिक बचत बैंक जमा खाता जिसे शून्य शेष से खोला जा सकता है, की रूपरेखा और कार्यान्वयन में वित्तीय समावेशन के सामाजिक सरोकार को देखते हुए, बैंकिंग से वंचित और गरीब लोगों का व्यापक रूप से ध्यान रखा गया है. • वरिष्ठ नागरिकों के लिए जुबली प्लस बचत खाता: समाज के बुजुर्ग सदस्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शून्य शेष बचत खाता डिजाइन किया है जिसमें सुविधाएं और फीचर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं. • महिलाओं के लिए सुपर शक्ति बचत खाता: महिलाओं के बचत और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक ने महिलाओं के लिए एक विशेष बचत खाता डिजाइन किया है जिसमें दी गई सुविधाओं और फीचर के संबंध में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है. • स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए चालू खाता : कारोबार परिवेश के विकास में स्टार्ट-अप उद्यमों द्वारा निर्भाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका और कारोबार स्थापना के आरंभिक चरण में उनके परिचालित चालू खाते में उच्च शेष बनाए रखने में होने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक विशेष चालू खाता डिजाइन किया है, जिसमें ऐसी संस्थाओं के लिए शेष बनाए रखने के लिए कोई प्रभार लागू नहीं है. • कौशल ऋण योजना - शिक्षा ऋण के अंतर्गत: आईडीबीआई बैंक स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना ऑफर कर रहा है. • राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के दिशानिर्देशों के तहत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को शिक्षा ऋण: आईडीबीआई बैंक भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक शारीरिक रूप से विकलांग भारतीय नागरिकों के लिए शिक्षा ऋण योजना ऑफर कर रहा है. यह योजना विकलांग व्यक्तियों को पारंपरिक व्यवसायों और उद्यमशीलता के क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्ञान प्रदान करती है. • ऊर्जा बचत आवास पुनर्वित्त योजना - आवास ऋण के तहत: इस योजना के तहत शहरी इलाकों में प्रमाणित आवासीय भवन परियोजनाओं में ऊर्जा बचत वाली नई आवासीय आवास इकाइयों की खरीद के लिए प्राथमिक ऋणदात्री संस्थानों (पीएलआई) द्वारा व्यक्तियों को संवितरित ₹ 50 लाख तक के आवास ऋण को कवर किया जाता है.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> आईडीबीआई बुनकर मुद्रा योजना: बैंक ने विशेष रूप से सात क्लस्टरों अर्थात् महेश्वर (मध्य प्रदेश), शांतिपुर (पश्चिम बंगाल), बरगढ़ (ओडिशा), कांचीपुरम (तमिलनाडु), शाउलकुची (असम), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और धर्मावरम (आंध्र प्रदेश) में हथकरघा बुनकरों को ऋण देने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बुनकरों को पर्याप्त रूप से और समय पर सहायता प्रदान करना है ताकि वे आसान और कम लागत पर अपनी क्रेडिट आवश्यकताओं, निवेश आवश्यकताओं (मीयादी ऋण) और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना सात विशिष्ट क्लस्टरों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लागू की गई है। योजना के तहत ₹ 50,000 तक की कार्यशील पूंजी की सीमा वाले ग्राहकों को रुपये डेबिट कार्ड जारी किया जा रहा है। कृषि उत्पादक कंपनियों के लिए कृषि उन्नति वित्तपोषण: देश के तीन-चौथाई से अधिक किसान छोटे और सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) हैं तथा उनके पास टुकड़ों में जमीन है। उनके पास पूंजी की कमी है, जिसके चलते मशीनों / प्रौद्योगिकी का कम उपयोग कर पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और लाभप्रदता कम होती जाती है। छोटे किसानों/ उत्पादकों को सामूहिक सौदा करने की शक्ति प्रदान करने हेतु कृषि के निवेश और उत्पादन दोनों स्तरों पर एकीकरण के लिए कृषि उत्पादक कंपनी (एफपीसी) के गठन को प्रोत्साहित किया जाता है। आईडीबीआई बैंक एफपीसी के लिए एक विशिष्ट उत्पाद शुरू करने वाले पहले बैंकों में से एक था, जिसने उनके सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करते हुए ऋण सुविधाओं के लिए उदार शर्तों की पेशकश की। कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / एफपीसी का गठन और उनका विकास लाभदायक खेती के लिए देश के लघु एवं सीमांत किसानों को सक्षम बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जाता है। कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अग्रिम वित्तपोषण: क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म परियोजनाएं जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक्जीक्यूटिव बोर्ड के पास पंजीकृत या पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं और चालू हो गई हैं या चालू होने के करीब हैं, से कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अग्रिम वित्तपोषण।
<p>ख. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे उपलब्ध कराएं (वैकल्पिक):</p> <ol style="list-style-type: none"> समूची मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से अब तक सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण के दौरान कमी? पिछले वर्ष से अब तक ग्राहकों द्वारा उपयोग (ऊर्जा, पानी) के दौरान जो कमी प्राप्त की गई है? 	<p>लागू नहीं</p>

ग.	क्या कंपनी के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए तैयार प्रक्रिया है (परिवहन सहित)?	लागू नहीं
ii.	यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत वास्तव में सोर्स किया गया? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे प्रदान करें.	
घ.	क्या कंपनी ने अपने कार्य-स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?	लागू नहीं
ड.	यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?	लागू नहीं
च.	क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण के लिए कोई व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों की पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, >10% के रूप में). साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे प्रदान करें.	लागू नहीं

3 सिद्धान्त 3: कारोबार को अपने सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए

क.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं.	18,187
ख.	कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/ अनियमित आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या बताएं.	467
ग.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं.	5,155
घ.	कृपया शारीरिक रूप से निःशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं.	350
ड.	क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?	प्रथा के अनुसार, बैंक ने किसी भी यूनियन/ संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन/ संघ का दर्जा नहीं दिया है.
च.	आपके स्थायी कर्मचारियों में कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	उपर्युक्त 'ड' को देखते हुए लागू नहीं.
घ.	कृपया बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें.	

श्रेणी	2016-17 के दौरान दर्ज शिकायतें	यथा 2016-17 की समाप्ति पर लंबित शिकायतें
i. बाल मजदूरी/ जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
ii. यौन उत्पीड़न	6	6*
iii. भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य
च. पिछले वर्ष उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?		
i. स्थायी कर्मचारी	66%	
ii. स्थायी महिला कर्मचारी	68%	
iii. अनियमित/ अस्थायी/ संविदा कर्मचारी	50%	
iv. शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारी	66%	

* पिछले वर्ष की 2(दो) शिकायतें शामिल हैं.

4 सिद्धान्त 4: कारोबार को सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, विशेष रूप से उनके लिए, जो सुविधाहीन, कमजोर तथा हाशिए पर हैं.

क.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मैप किया है? हाँ/नहीं.	हाँ
ख.	उपर्युक्त में से कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर हितधारकों की पहचान की है?	हाँ

<p>ग. क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए के हितधारकों से संबद्ध कोई विशेष पहल की है. यदि हाँ, तो उनके बारे में करीब 50 शब्दों में ब्योरा दें.</p>	<p>बैंक भारत सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति का पूरी तरह अनुपालन करता है. बैंक ने अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी)/ शारीरिक रूप से अक्षम (पीडब्ल्यूडी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए महा प्रबंधक और उप महा प्रबंधक रैंक के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) और अंचल संपर्क अधिकारियों (जेडएलओ) को नियुक्त किया है, जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन और उनकी शिकायतों के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करते हैं. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पीडब्ल्यूडी के लिए अलग रोस्टर रखता है.</p> <p>बैंक देश के बैंकिंग रहित/ कम बैंकिंग जनसंख्या के लिए कई वित्तीय समावेशन पहल कार्य करता है, जैसे-वित्तीय साक्षरता शिविरों का संचालन, बैंकिंग रहित ग्रामीण केन्द्रों में ग्रामीण वित्तीय समावेशन शाखाएँ खोलना, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाते खोलना, आदि.</p> <p>बैंक सभी ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों, निरक्षर व्यक्तियों और पेंशनभोगियों जैसे विशेष ग्राहकों की शिकायतों पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाए.</p> <p>इसके अलावा, बैंक अपनी सीएसआर नीति के अनुसार समाज के वंचित वर्गों के जीवन में भौतिक, दृश्य और स्थायी बदलाव लाने के लिए और समग्र रूप से समाज कल्याण में लगातार सकारात्मक योगदान देने के लिए पात्र परियोजनाओं को निधि प्रदान करता है.</p>
--	--

5 सिद्धांत 5: कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

<p>क. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?</p>	<p>मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करने वाली बैंक की विभिन्न नीतियाँ केवल बैंक के परिचालन पर लागू होती हैं तथा सहायक संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, एनजीओ आदि पर लागू नहीं होती है.</p> <p>बैंक मानवाधिकारों पर लागू होने वाले सभी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है.</p> <p>कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच): बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति लागू की है. बैंक ने यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियाँ बनाई हैं. कर्मचारियों में पीओएसएच के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से परस्पर संवाद वाला ई-लर्निंग मॉड्यूल बैंक के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (ओजस) के तहत रखा गया है और पीओएसएच पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी.</p>
---	---

		<p>शिकायतों का निवारण: बैंक यह स्वीकार करता है कि ग्राहक बैंक के मुख्य संघटक हैं और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. इसके लिए बैंक ने 'ग्राहक सेवा नीति', 'शिकायत निवारण नीति', 'ग्राहक सेवाविच्छेद नीति', 'क्षतिपूर्ति नीति', 'ग्राहक अधिकार नीति' तैयार की है और 'नागरिक चार्टर' भी लागू किया है. साथ ही, बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसने ग्राहकों के प्रति बैंक के प्रतिबद्धता कोड तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रति बैंक के प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है.</p>
<p>ख.</p>	<p>पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत कितना रहा?</p>	<p>2016-17 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित छह शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से दो शिकायतों का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया.</p> <p>अन्य हितधारकों की शिकायतों हेतु कृपया सिद्धांत 1 का बिंदु संख्या 2 देखें.</p>

6 सिद्धान्त 6: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए तथा इसमें सुधार का प्रयास करना चाहिए

<p>क.</p>	<p>क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?</p>	<p>यह नीति केवल आईडीबीआई बैंक पर लागू होती है.</p> <p>बैंक ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कागजरहित इको-फ्रेंडली प्रौद्योगिकी के प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण आदि जैसे उपायों को लागू कर पर्यावरण का ध्यान रखता है, इसकी रक्षा करता है और इसमें सुधार के प्रयास करता है. साथ ही, बैंक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और 1 मई 2012 से प्रभावी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली, 2011 का भी पालन कर रहा है.</p>
<p>ख.</p>	<p>क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निपटान के लिए रणनीतियाँ/ पहल-कार्य हैं? हाँ/ नहीं. यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें.</p>	<p>हाँ. आईडीबीआई बैंक ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के अपने प्रयासों में देश के विभिन्न हिस्सों में सौर ऊर्जा प्रणालियों और नवोन्मेषी कार्यक्रमों के रूप में स्वच्छ ऊर्जा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए संगठनों की मदद की है.</p>

		पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2016-17 में किए गए सीएसआर कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>गतिविधि/ संगठन का नाम</th> <th>उद्देश्य</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, (टेरी)</td> <td>टेरी के 'लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसके तहत उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में 100 से अधिक गांवों के 5,000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एमएसई)</td> <td>एमएसई परिसर में 'उत्कृष्टता केंद्र' पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज</td> <td>इसके सिकंदराबाद परिसर में छत के ऊपर सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>दिलासा संस्था</td> <td>रेलगाँव ब्लॉक, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र के सोनुर्ली और वालनगर गांव में चौथे वाटरशेड विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	गतिविधि/ संगठन का नाम	उद्देश्य	1.	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, (टेरी)	टेरी के 'लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसके तहत उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में 100 से अधिक गांवों के 5,000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं.	2.	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एमएसई)	एमएसई परिसर में 'उत्कृष्टता केंद्र' पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता	3.	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज	इसके सिकंदराबाद परिसर में छत के ऊपर सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	4.	दिलासा संस्था	रेलगाँव ब्लॉक, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र के सोनुर्ली और वालनगर गांव में चौथे वाटरशेड विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता
क्र. सं.	गतिविधि/ संगठन का नाम	उद्देश्य															
1.	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, (टेरी)	टेरी के 'लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसके तहत उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में 100 से अधिक गांवों के 5,000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं.															
2.	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एमएसई)	एमएसई परिसर में 'उत्कृष्टता केंद्र' पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता															
3.	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज	इसके सिकंदराबाद परिसर में छत के ऊपर सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता															
4.	दिलासा संस्था	रेलगाँव ब्लॉक, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र के सोनुर्ली और वालनगर गांव में चौथे वाटरशेड विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता															
ग.	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान तथा आकलन करती है? हाँ/ नहीं.	हाँ. पर्यावरणीय जोखिम आकलन बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है. मौजूदा ऋण जोखिम निगरानी नीति मंजूरी पत्र में उपयुक्त शर्तों का निर्धारण कर व्यापक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि सभी सहायता प्राप्त ग्राहक स्थायी आधार पर पर्यावरण संबंधी सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.															
घ.	क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें. साथ ही, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?	आईडीबीआई बैंक सरकारी क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसने स्वच्छता विकास तंत्र (सीडीएम) पर कार्य करने के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया है. बैंक की कार्बन क्रेडिट सेवाओं में स्वच्छता विकास तंत्र परियोजनाओं के मूल्यांकन, निधीयन, पंजीकरण के लिए तकनीकी सलाहकारी सेवाएं और कार्बन क्रेडिट की बिक्री के लिए वाणिज्यिक परामर्शदात्री सेवाएं, आदि शामिल हैं. बैंक ने अनुमानित कार्बन क्रेडिट प्राप्ति को ध्यान में रखकर कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक नवोन्मेषी उत्पाद 'कार्बन क्रेडिट प्राप्ति पर प्रारंभिक वित्त' शुरू किया है. इस उत्पाद को पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी)-21 के तहत नए दिशानिर्देशों के अनुसार आशोधित किया जाएगा.															

<p>ड. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं. यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दे.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बैंक के ध्येय "हरित बैंक बनने के लिए निरंतर प्रयासरत", वाक्य के अनुसार बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकियों अर्थात पवन और सौर पर आधारित संभावित हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पहल की है. आईडीबीआई बैंक ने लगभग 12 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है. • बैंक अप्रचलित आईटी उपकरणों के निपटान के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन करता है तथा बैंक ने इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार की है तथा इसे लागू किया है और अप्रचलित आईटी उपकरणों के सुरक्षित निपटान हेतु वेंडरों की नियुक्ति की है. • बैंक ने अपनी कई कारोबार प्रक्रियाओं को स्वचालित बना दिया है. साथ ही, कागजों की खपत कम करने के लिए बैंक कागज रहित बैठकें भी आयोजित करता है. • जहां कहीं भी संभव है, बैंक आंतरिक संप्रेषण (अनुमोदन, परिपत्र आदि) के लिए तथा बाहरी संप्रेषण के लिए ग्राहकों (खातों के मासिक विवरण, ई-मेल आदि), शेयरधारकों (वार्षिक रिपोर्ट), कारोबार भागीदारों, विनियामकों तथा सरकार आदि के साथ संप्रेषण में पेपर आधारित माध्यमों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग कर रहा है. • बैंक ने अपनी सभी शाखाओं/ कार्यालयों को निर्देश दिया है कि कागजों की खपत को कम करने के लिए वे उधारकर्ताओं/ वेंडरों आदि को भुगतान/ ऋणों का संवितरण केवल खातों में जमा/ आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से करें. • बैंक ने कागज की खपत कम करने के लिए कर्मचारियों से संबंधित लगभग सभी कार्यों जैसे वेतन, लाभ, दावों का भुगतान, उपस्थिति दर्ज करना, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन आदि को स्वचालित किया है. • सर्वर वर्चुलाइजेशन: डेटा केन्द्रों में सर्वर फुटप्रिंट कम करने के लिए बैंक ने सर्वर वर्चुलाइजेशन तंत्र लागू किया है जिसके माध्यम से वर्चुलाइज्ड वातावरण में एप्लिकेशन को लाकर पर्याप्त रूप से वैयक्तिक बाह्य सर्वरों की संख्या में कमी की गई है. इसके परिणामस्वरूप विद्युत की खपत और ऊष्मा संचारण में कमी हुई है. <p>बिजली और पानी के उपयोग में कमी के लिए कुछ समय पहले निम्नलिखित पहल कार्य किए गए हैं :</p> <p>कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई में</p> <ul style="list-style-type: none"> • बिजली की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा सक्षम वैरिएबल वोल्टेज वैरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) ड्राइव, माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित सिस्टम के साथ लिफ्टों का आधुनिकीकरण • वर्तमान में कार्यरत केंद्रीकृत एसी संयंत्र के लिए पुराने चिल्लर पंप्स (8 x 75 एचपी) का प्रतिस्थापन • पारंपरिक लाइटों के स्थान पर टी-5/ एलईडी लाइटों को लगवाना • कूलिंग टॉवर मेक अप वॉटर हेतु उपयोग किए गए पानी के पुनः उपयोग के लिए सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> जल संरक्षण के लिए सेंसर-आधारित वॉश बेसिन और यूरिनल वाटर फ्लो बैंक के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) कार्यालय भवन में : सामान्य लाइटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 किलोवाट बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल स्थापित किए गए हैं. प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लाइट फिटिंग और निवासी सेंसर का प्रयोग किया गया है. एयर कंडीशनिंग के लिए ऊर्जा बचत स्कू चिलर्स का प्रयोग किया गया है. पानी बचाने के लिए शौचालयों में सेंसर संचालित पानी के नल और दोहरे फ्लश सिस्टम लगाए गए हैं. वर्षा का जल एकत्र करने के लिए वर्षा जल संरक्षण किया जाता है, जिससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी. जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद में: बैंक के प्रशिक्षण संस्थान जेएनआईबीएफ, हैदराबाद में सोलर वाटर हीटर लगाए गए हैं. <p>उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक अपनी सभी नई परियोजनाओं और मौजूदा परिसरों के नवीनीकरण में जल और ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपना रहा है.</p>
च.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा जनरेट उत्सर्जन/ अपशिष्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?	सेवा क्षेत्र में होने के कारण बैंक के परिचालनों से न्यूनतम उत्सर्जन/ अपशिष्ट जनरेट होता है.
छ.	सीपीसीबी/ एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है) हैं.	शून्य
7 सिद्धांत 7: जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने वाले कारोबार, जवाबदेही के साथ करने चाहिए		
क.	क्या आपकी कंपनी किसी कारोबार और वाणिज्य मंडल अथवा संस्थानों का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल मुख्य नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार किया जाता है : (3 तक)	हाँ. कुछ संस्थान/ संघ जिनका आईडीबीआई बैंक सदस्य है, निम्नानुसार हैं : <ul style="list-style-type: none"> एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की विकास वित्तीय संस्थाओं का संघ (एडीएफआईएपी) भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
ख.	क्या आपने उपर्युक्त संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण में सुधार या प्रगति के लिए समर्थन/ उस हेतु प्रचार किया है? हाँ/ नहीं; यदि हाँ, तो मुख्य क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दें. (ड्रॉप बॉक्स: सरकार एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, भोजन सुरक्षा, स्थाई कारोबार सिद्धांत, अन्य)	बड़ा बैंक होने के कारण बैंक हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं और औद्योगिक निकायों अर्थात् आईबीए के साथ बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों, वित्तीय समावेशन आदि के लिए जवाबदेही के साथ संबद्ध रहा है.

8 सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास में सहयोगी होना चाहिए

<p>क. क्या सिद्धांत 8 के संबंध में नीति के अनुसार कंपनी के पास कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल-कार्य/ परियोजना है. यदि हाँ, तो उनके ब्योरे.</p>	<p>भारत सरकार और रिजर्व बैंक के मिशन के अनुसार बैंक ने देश की कम बैंकिंग/ बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनसंख्या के वित्तीय समावेशन के पथ पर बढ़ना आरंभ कर दिया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहल-कार्य किए गए हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनस टेक्नॉलॉजी (आईसीटी) समर्थित कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से लगभग 300 से अधिक बैंक-रहित सब सर्विस एरिया (एसएसए) (लगभग 1200 गांवों को मिलाकर) में आधारभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. • बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक रहित ग्रामीण स्थानों में 253 ग्रामीण वित्तीय समावेशन शाखाएं खोली हैं. • प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत देश भर में 11 लाख से अधिक बेसिक सेविंग डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले गए हैं जिनमें ₹ 225 करोड़ (औसत शेष ₹1,910) की जमा राशि है. • वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन का एक अभिन्न भाग है. बैंक की ग्रामीण शाखाएं अपने सेवा क्षेत्र में बाह्य वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन करती हैं. 2016-17 के दौरान, लगभग 490 कैंपों का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 8,800 ग्रामीणों ने भाग लिया. बैंक वित्तीय उत्पादों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन करता है. ऐसे लगभग 250 से अधिक नाटकों का आयोजन किया जा चुका है. इसके अलावा, विद्यार्थियों के लिए गुजरात/ मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र के विद्यालयों में 170 से अधिक वित्तीय साक्षरता कैंप भी आयोजित किए गए हैं. • बैंक ने देश भर के लगभग 660 स्थानों पर किसान संगोष्ठियों का आयोजन किया. इन किसान संगोष्ठियों में लगभग 30,000 किसानों ने भाग लिया. किसान संगोष्ठियों में किसानों को डिजिटल बैंकिंग तथा कैशलेस लेनदेनों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई. • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योग को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए 1.5 लाख से अधिक खाताधारकों को ₹ 1700 करोड़ से अधिक का सूक्ष्म ऋण प्रदान किया गया. <p>कई वित्तीय समावेशन पहल-कार्यों की शुरुआत करने के अलावा बैंक अपने सीएसआर पहल-कार्यों के माध्यम से बहुआयामी प्रभाव रखने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए दीर्घकालिक और समग्र विकास के लिए भी योगदान करता है. अभी तक, 2016-17 के दौरान, बैंक ने कई सीएसआर गतिविधियों का संचालन किया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना, बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, आजीविका के अवसरों में वृद्धि और व्यावसायिक और रोजगार कौशल को समुन्नत करना है.</p>
--	---

<p>ख.</p>	<p>आंतरिक टीम/ अपने फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संस्थाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से क्या कोई कार्यक्रम/ परियोजनाएं चलाई जाती हैं?</p>	<p>कार्यक्रम, बाहरी एजेंसियों के सहयोग से आंतरिक टीम द्वारा, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के प्रावधान और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों के कार्मिकों के लिए चलाए जाते हैं।</p> <p>समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास से संबंधित सीएसआर परियोजनाएं अधिकांशतः एनजीओ, सरकारी संस्थाओं तथा कुछ सीमा तक बैंक की शाखाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं।</p>
<p>ग.</p>	<p>क्या आपने अपने पहल-कार्यों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?</p>	<p>सीएसआर पहल-कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन कार्यान्वयनकर्ता भागीदार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, बैंक की वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत प्रभाव का मूल्यांकन निम्नानुसार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. बैंक और सरकार को सूक्ष्म बीमा योजनाओं और पेंशन योजनाओं द्वारा वंचित लोगों को वित्तीय मुख्य धारा से विधिवत रूप से जोड़ने में मदद मिली है। <ul style="list-style-type: none"> • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 10 लाख बैंक खाता धारकों का नामांकन कराया गया है। • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) के अंतर्गत 5 लाख से अधिक खाता धारकों का नामांकन कराया गया है। • अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत 0.50 लाख से अधिक बैंक खाता धारकों का नामांकन कराया गया है। ii. कुल 112 लाख सक्रिय बचत बैंक खातों में से 44.03 लाख खातों (39.3%) तथा 7.86 लाख सक्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में से 4.29 लाख खातों (54.6%) को आधार से जोड़ा गया, जिससे सब्सिडी वितरण और लाभ को आधार के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जमा कर, लीकेज और चोरी को बंद कर सरकार के संकल्प को पूरा करने हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ। iii. यथा 31 मार्च 2017 को बैंक ने 30 लाख से भी अधिक मूल बचत बैंक खाते खोले थे जो हैं जो बैंक के वित्तीय समावेशन संबंधी पहल-कार्यों के अंतर्गत शून्य शेष वाले खाते हैं। iv. महाराष्ट्र के सतारा जिले में बैंक का ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्योन्मुख प्रशिक्षण का आयोजन करता है। आरएसईटीआई ने अपनी शुरुआत से अब तक 3,657 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

घ.	<p>सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में राशि तथा चालू परियोजनाओं का विवरण?</p>	<p>प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से की जाने वाली आईडीबीआई बैंक की समुदायिक विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है:</p> <table border="1" data-bbox="837 362 1452 1667"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th> <th>गतिविधि/ संगठन का नाम</th> <th>उद्देश्य</th> <th>2016-17 में किया गया व्यय (₹ लाख)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, (टेरी), नई दिल्ली</td> <td>‘लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स’ कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसका उद्देश्य चार राज्यों के चुनिन्दा गांवों में 5000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम प्रदान करना है.</td> <td>32.02</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट के लिए आवास</td> <td>महाराष्ट्र के नांदेड़ तथा उस्मानाबाद में पानी लाने-लेजाने में सुविधा प्रदान करने के लिए 600 ग्रामीण महिलाओं को वाटर व्हील प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता.</td> <td>11.75</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा चंदौली जिले में सीएसआर कार्यकलाप</td> <td>सड़कों, सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर ऊर्जा चालित लैंप पोस्ट, शौचालयों तथा सबमर्सीबल वाटर पंप का प्रावधान करने तथा विद्यालय भवन के मरम्मत जैसे विभिन्न सीएसआर कार्यकलाप करने के लिए वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले के भभौरा में दो गांवों को गोद लेना.</td> <td>70.49</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि</td> <td>असम के मोरीगांव जिले में आदर्श ग्राम का विकास</td> <td>3.76</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. स.	गतिविधि/ संगठन का नाम	उद्देश्य	2016-17 में किया गया व्यय (₹ लाख)	1.	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, (टेरी), नई दिल्ली	‘लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स’ कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसका उद्देश्य चार राज्यों के चुनिन्दा गांवों में 5000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम प्रदान करना है.	32.02	2.	ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट के लिए आवास	महाराष्ट्र के नांदेड़ तथा उस्मानाबाद में पानी लाने-लेजाने में सुविधा प्रदान करने के लिए 600 ग्रामीण महिलाओं को वाटर व्हील प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता.	11.75	3.	उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा चंदौली जिले में सीएसआर कार्यकलाप	सड़कों, सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर ऊर्जा चालित लैंप पोस्ट, शौचालयों तथा सबमर्सीबल वाटर पंप का प्रावधान करने तथा विद्यालय भवन के मरम्मत जैसे विभिन्न सीएसआर कार्यकलाप करने के लिए वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले के भभौरा में दो गांवों को गोद लेना.	70.49	4.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि	असम के मोरीगांव जिले में आदर्श ग्राम का विकास	3.76
क्र. स.	गतिविधि/ संगठन का नाम	उद्देश्य	2016-17 में किया गया व्यय (₹ लाख)																			
1.	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, (टेरी), नई दिल्ली	‘लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स’ कार्यक्रम को वित्तीय सहायता जिसका उद्देश्य चार राज्यों के चुनिन्दा गांवों में 5000 घरों में सोलर लाइटिंग सिस्टम प्रदान करना है.	32.02																			
2.	ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट के लिए आवास	महाराष्ट्र के नांदेड़ तथा उस्मानाबाद में पानी लाने-लेजाने में सुविधा प्रदान करने के लिए 600 ग्रामीण महिलाओं को वाटर व्हील प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता.	11.75																			
3.	उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा चंदौली जिले में सीएसआर कार्यकलाप	सड़कों, सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर ऊर्जा चालित लैंप पोस्ट, शौचालयों तथा सबमर्सीबल वाटर पंप का प्रावधान करने तथा विद्यालय भवन के मरम्मत जैसे विभिन्न सीएसआर कार्यकलाप करने के लिए वाराणसी जिले में सुजाबाद तथा चंदौली जिले के भभौरा में दो गांवों को गोद लेना.	70.49																			
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि	असम के मोरीगांव जिले में आदर्श ग्राम का विकास	3.76																			
ड.	<p>क्या आपके इन समुदायिक विकास के पहल-कार्यों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँ हैं? कृपया करीब 50 शब्दों में विवरण दें.</p>	<p>समुदाय के विकास को ध्यान में रखकर सीएसआर गतिविधियों को सभी स्थानीय आबादी और जमीनी स्तर के लाभार्थियों सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है. इस तरह समुदाय को शुरुआत में ही शामिल किया जाता है और परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि समुदाय द्वारा इन पहल-कार्यों को सफलतापूर्वक अपनाया जा सके.</p>																				

9 सिद्धान्त 9: कारोबार को उत्तरदायी तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा हुआ और उन्हें महत्व देने वाला होना चाहिए.

क.	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितनी प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले लंबित हैं.	प्राप्त कुल शिकायतों में से यथा 31 मार्च 2017 को लगभग 1% अर्थात् 622 शिकायतें लंबित थीं.
ख.	क्या कंपनी स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है. हाँ/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियाँ (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
ग.	क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित कार्यप्रणालियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/ या प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के लिए किसी हितधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित है. यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.	लागू नहीं
घ.	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि रूझान के बारे में कुछ किया है?	बैंक निरंतर आधार पर ग्राहक फीडबैक प्राप्त करता है. साथ ही बैंक प्रति माह शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति की बैठकों (बीएलसीएससी) के जरिए शाखाओं में सेवा की गुणवत्ता पर ग्राहक फीडबैक भी प्राप्त करता है जिनमें समाज के हर वर्ग के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है. ग्राहकों के सुझावों का उपयोग ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया जाता है. इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंकिंग संहिता तथा मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा बैंक की शाखाओं के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर बैंक को ग्राहक फीडबैक के मापदंडों के अनुसार उच्च रेटिंग दी गई है.

Business Responsibility Report

Sr. No.	Particulars	Details	
A. General Information about the Bank			
1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L65190MH2004GOI148838	
2	Name of the Company	IDBI Bank Limited	
3	Registered address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005	
4	Website	www.idbi.com	
5	E-mail id	idbiequity@idbi.co.in	
6	Financial Year reported	2016-17	
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Code: 64191-IDBI Bank is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949.	
8	List three key products/ services that the Company manufactures/ provides (as in balance sheet)	1. Corporate/ Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Treasury Operations	
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	1896 branches	
	a. Number of International Locations (Provide details of major 5)	The Bank has an overseas branch at DIFC, Dubai and an international branch at GIFT City, Gujarat, India.	
	b. Number of National Locations	1894	
10	Markets served by the Company (Local/ State/ National/ International)	The Bank serves customers in all locations where it has presence.	
B. Financial Details of the Company			
1	Paid up Capital (in ₹ lakh)	2,05,881.51	
2	Total Turnover (in ₹ lakh)	31,75,896.60	
3	Total profit/ loss after taxes (in ₹ lakh)	(5,15,813.97)	
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%) as on March 31, 2017	The average net profit/ loss of the Bank for the last three financial years worked out to a loss of ₹ 698 crore. However, as a pro-active initiative, the Bank had CSR spends of ₹ 4.35 crore during 2016-17.	
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:		
Sr. No.	Activity	No. of CSR Projects	Amount (₹ lakh)
a.	Health	6	122.75
b.	Rural Development	2	74.25
c.	Education	10	111.04
d.	Socio-Economic Development	1	11.75
e.	Environment	4	55.27
f.	Promotion of Sports	2	59.95
TOTAL		25	435.01

Expenditure incurred under various heads during 2016-17 is as follows:

Health

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1.	Tata Medical Centre	Financial support towards i) Phase II expansion bay 6-beds, ii) Treatment of 40 underprivileged/ economically weak patients, iii) Palliative medicine unit with admission facilities for 25 patients	100.00
2.	Royal Commonwealth Society for the Blind (Sightsavers)	Financial support providing quality primary eye care services	13.97
3.	Ramakrishna Math	Financial support for purchase of one X-ray machine and supporting digital system for their charitable dispensary	6.31
4.	Office of Executive Officer, Jhargram Municipality	Construction of public toilet for tribal people	1.49
5.	Eklavya Model Residential School	Installation of automated vending machine for sanitary napkins (Double Cylinder) and incinerator machine	0.73
6.	Red Cross	Providing food for the poor people	0.25
Total			122.75

Rural Development

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1.	CSR Activities in Varanasi and Chandauli districts of Uttar Pradesh	Adoption of two villages - Suzabad in Varanasi district and Bhabhaura in Chandauli district for undertaking various CSR activities viz. construction of roads, community hall, provision of solar light lamp posts, toilets and submersible water pumps, and refurbishment of school building	70.49
2.	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi	Development of Model Village	3.76
Total			74.25

Education

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1.	Support to State Mid Day Meal Office	Financial assistance to State Mid Day Meal (MDM) office for purchase of 5,000 weighing machines	44.10
2.	Apang Kalyan Shikshan Sanstha	Financial assistance for purchasing classroom furniture, solar system and other materials for the school	1.20
3.	North Eastern Development Finance Corporation (NEDFi)	Financial support for setting up one showroom for marketing of designer candles and other local handicrafts and supporting its operations cost up to three years	4.80
4.	Rehabilitation Projects in Uttarakhand (Anganwadi Centres)	Construction of five Anganwadi Centres (AWCs) or Auxilliary Nurse Midwife (ANM) centres at disaster affected sites identified by the district administration of Pithoragarh	17.36
5.	Mara T.T. Chako & Abraham Charitable Trust	Financial assistance towards completion of the remaining portion of disabled friendly special school and setting up of vocational training centre for mentally and physically challenged children in Saiha district of Mizoram	12.00
6.	All India Movement (AIM) for Seva	Financial support to Free Student Home, Lucknow, having 46 students for a period of one year	3.45

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
7.	Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)	Conducting skill development programmes in Karnali Village Panchayat, Gujarat	15.13
8.	NAB Workshop for the Blind, Maharashtra	Financial assistance towards awarding 30 Braille shorthand machines to 30 stenography students on successful completion of the course and one laser printer and 10 desktop computers for MS-CIT and English and Marathi stenography course	7.69
9.	Deputy Commissioner (DC) Office Saiha, Mizoram	Installation of 223 water filters in schools in Saiha district	4.46
10.	Rotary Club of Navi Mumbai Sunrise Society	Sponsoring education costs for 10 children	0.85
Total			111.04

Socio-Economic Empowerment

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1.	Habitat for Humanity India Trust	Financial support for providing water wheels to rural women for facilitating ease in carrying water in Nanded and Osmanabad districts of Maharashtra	11.75

Environment

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1.	The Energy and Resources Institute (TERI)	Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' programme wherein 5,000 households in select villages across four states were provided solar lighting systems	32.02
2.	Madras School of Economics (MSE)	Financial support for installing solar power system for 'Centre of Excellence' in MSE's campus	6.25
3.	Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences	Financial support towards installation of roof-top solar power panel	12.00
4.	Dilasa Sanstha	Financial support for executing 4 th watershed development programme	5.00
Total			55.27

Promotion of Sports

Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	Amount (₹ lakh)
1.	Directorate of Youth Affairs and Sports, Government of Tripura	Financial assistance to Directorate of Youth Affairs and Sports, Government of Tripura for purchase of gymnastics equipment for their State-run sports academy	9.95
2.	National Sports Development Fund	Contribution to National Sports Development Fund	50.00
Total			59.95

C. Other Details

1.	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes. The Bank has five domestic subsidiaries namely, IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd., IDBI Intech Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd.
----	--	---

2	Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).	No
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].	No

D. BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible for BR

a. Details of the Director/ Director responsible for implementation of the BR policy/ policies	
DIN Number	02611496
Name	Shri Krishna Prasad Nair
Designation	Deputy Managing Director
b. Details of BR Head	
DIN Number	00064934
Name	Shri Alope Sengupta
Designation	Chief General Manager
Tel. No.	+91-22-66552300
Email ID	aloke.sengupta@idbi.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/ policies (Reply in Y/ N)

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
a.*	Do you have a policy/ policies for...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
b.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
c.**	Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
d.	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
e.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
f.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y\$	Y#
g.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
h.	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
i.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
j.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The heads of various departments are responsible for effective implementation of the policies. The Compliance Department monitors the adherence to implementation of policies mandated by RBI.								

Note:

- * The various policies of the Bank, which are formally put in place, govern different functions of the Bank directly or indirectly.
 Principle 1 – The Bank mainly follows the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission.
 Principle 2 – Most of the activities under Principle 2 are governed by the Bank’s Credit Policy and product guidelines which are confidential.
- ** The policies of the Bank are in conformity with guidelines issued by regulatory and statutory bodies and therefore conform to national standards.
- \$ Link to CSR Policy - <http://www.idbi.com/csr-policy.asp>
- # The policies of the Bank viz. Customer Rights Policy, Grievance Redressal Policy, Citizens Charter and the BCSBI codes are available for public viewing under Customer Education through this link: <http://www.idbi.com/customer-carecentre.asp>

2a. If answer to Sr. No. 2 against any principle, is ‘No’, please explain why: (Tick up to 2 options)

(Reasons for not having policy for any of the principle(s) needs to be mentioned)

a.	The company has not understood the Principles	Reason for not having a policy for P7:
b.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	The Bank does not have a documented policy for P7. However, it has always been associated with the regulators and policymakers in a responsible manner. The Bank has been a pioneer in the area of development financing and has taken a lead role in setting up the financial architecture of India. Besides, the Bank has been associated with the policymakers for improvement in the areas of banking sector reforms, financial inclusion etc.
c.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	
d.	It is planned to be done within next 6 months	
e.	It is planned to be done within the next 1 year	
f.	Any other reason (please specify)	

3 Governance related to BR

a.	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	The BR performance of the Bank is submitted on an annual basis to the Board.
b.	Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, the Bank publishes a Business Responsibility Report. The BR Report can be viewed at www.idbi.com . This report is being published annually, starting from 2015-16, as a part of Bank’s Annual Report.

E. Principle-wise performance

1 Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

a.	Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.	Yes, it covers the Bank only. The Bank has effective mechanism in place to check corruption, malpractices and misappropriation of funds. The Bank has framed the internal guidelines and procedures to deal with Vigilance matters in conformity with Central Vigilance Commission (CVC) guidelines. All the latest circulars/ guidelines pertaining to vigilance matters in general or specific to Banks issued by CVC are hosted on the Bank’s Intranet for benefit of all employees. Further, these guidelines have been compiled in the form of Vigilance Manual for the Bank, which is updated annually.
----	---	--

With a view to strengthening preventive vigilance in the Bank, the Annual Action Plan (AAP) for the Vigilance Department is prepared every financial year elaborating the gamut of activities to be undertaken focusing mainly on preventive vigilance.

The gist of such measures is as under:

- **Annual Returns of Assets and Liabilities (ARALs) filed by officers**
 - a) Online submission of ARAL has been made mandatory.
 - b) To undertake sample scrutiny of the ARALs submitted by officers of the Bank which includes all officers coming under the CVC's jurisdiction i.e. General Managers (Grade E) & above and 10% of the remaining ARALs.
- **Agreed List of Suspected Officers (ALSO)**
An agreed list of officers against whom there are complaints, doubts or suspicion relating to their honesty or integrity is prepared annually in consultation with the CBI authorities.
- **List of Officers of Doubtful Integrity (LODI)**
As per CVC guidelines, list of officers of Doubtful integrity is prepared/ reviewed annually.
- **Identification of Sensitive Posts and Rotation of Staff**
Identification of sensitive posts is done annually and implementation of job rotation policy of officials in such posts is carried out in the Bank by obtaining monthly/ quarterly feedback from various verticals of the Bank in this regard.
- **Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the CVC in monthly/ quarterly reports**
It is ensured by the HR Department that the officers appearing in ALSO/ LODI lists are not posted on sensitive assignments which is monitored by Vigilance Department.
- **Leveraging of Technology**
As per CVC guidelines for improving vigilance administration by leveraging technology, all application forms/ proforma are made available on the Bank's website in downloadable formats. All documents needed to be enclosed and the information to be provided are clearly explained on the website and is also part of the application form. Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) as advised by the Ministry of Finance for uniform implementation in public sector banks (PSBs) has been made active. Tenders/ Contracts awarded are displayed on the Bank's website on monthly basis. Improvement in Finacle system to plug security loopholes is continuously effected. Fraud Monitoring System has been put in place as a tool to control/ prevent frauds.

- **CTE Type Inspections**
 Vigilance Department conducts studies and scrutiny of contracts awarded on random basis for streamlining/ strengthening the existing systems and procedures like vendor payments, award of tenders and contracts, etc. The objective of such examination is not limited to the detection of malpractices and punishment of errant officials found guilty from vigilance angle but to help bring improvement in the systems/ procedures in the Bank so as to avoid recurrence of lapses/ irregularities in future contracts, apart from ensuring better technical and financial control.
- **Surveillance and Detection**
Surprise Vigilance Visit (SVV): In order to bring awareness in the rank and file to curb occurrence of frauds/ misappropriations, SVVs of selected branches are undertaken by the Vigilance Officers as envisaged in the Annual Action Plan.
Scrutiny of FTNPA, QM, OTS/ NS Cases: Scrutiny of First Time Non Performing Asset (FTNPA), Quick Mortality (QM), One Time Settlement (OTS)/ Negotiated Settlement (NS) cases is undertaken on a random basis. Such cases are scrutinised to ensure that discretionary powers are not exercised arbitrarily but in a fair and transparent manner and examination of the existing practices vis-à-vis systems and procedures in the Bank is undertaken with a view to eliminating or minimising factors which provide opportunities for corruption or malpractices and to ascertain whether the Staff Accountability exists.
- **Preventive Vigilance Committees (PVC)/ Zonal Preventive Vigilance Committees (ZPVC)**
 The Vigilance Department of the Bank ensures that ZPVC meetings are conducted at all 11 zones of the Bank once in a quarter to meet and discuss issues/ matters relating to vigilance. This envisages, apart from discussing the latest guidelines issued in areas with vigilance overtones, identification of weak spots/ areas in branches/ processing centres in respective zones which are vulnerable to frauds/ malpractices with a view to plugging the loopholes, if any, and tighten monitoring of deficient areas. These meetings are attended by officials from Vigilance Department as its nominees.
- **Vigilance Awareness Workshops**
 Vigilance Awareness Workshops are conducted across the Bank which are attended by Chief Vigilance Officer (CVO) of the Bank. At these workshops, it is emphasised that preventive vigilance is a proactive function with a focus on preventing frauds, malpractices, misappropriations and corruption in the Bank in particular, as also to avoid any financial or reputation loss to the Bank and strengthen the organisation in general.

	<ul style="list-style-type: none"> • Review of Vigilance Activities in the Bank <ul style="list-style-type: none"> - To monitor the overall progress in relation to all matters and to conduct structured meeting with MD & CEO on a quarterly basis and follow up the action points emerging at such structured meetings. - To submit a Memorandum to the Board of Directors on a quarterly basis on matters relating to review of vigilance activities in the Bank. • Prompt Punitive Action The Chief Vigilance Officer (CVO) monitors prompt punitive action by the Disciplinary Authorities against the delinquent officials. • Observance of Vigilance Awareness Week The Vigilance Awareness Week is observed annually as per CVC guidelines. Seminars, meetings, competitions etc. are organised at the branches/ offices during the week to disseminate awareness against corruption amongst staff/ public/ customers. • Vigilance Complaints The Chief Vigilance Officer (CVO) ensures investigation of complaints having vigilance overtones and takes appropriate action wherever required. 								
<p>Does it extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?</p>	<p>No, it doesn't extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others.</p>								
<p>b. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>The Bank handled a total of 58,388 customer complaints in 2016-17. Out of these, 57,328 customer complaints were received during 2016-17 and 1,060 complaints were brought forward from 2015-16. About 99% i.e. 57,766 complaints out of the total complaints handled were resolved and 622 complaints were pending as on March 31, 2017. The Bank has put in place a Board-approved Grievance Redressal Policy' which outlines the Bank's approach and commitment to complaint resolution within specified timelines.</p> <p>During 2016-17, 112 complaints were received by Vigilance Department of the Bank. All these complaints were examined/ investigated for vigilance overtones and resolved satisfactorily with the concurrence of the CVO.</p> <p>The details of shareholders' complaints are as under:</p> <table border="1" data-bbox="829 1719 1444 1864"> <thead> <tr> <th>Pending as on 01.04.16</th> <th>Received during 2016-17</th> <th>Redressed during 2016-17</th> <th>Pending as on 31.03.17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1,193</td> <td>1,193</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Pending as on 01.04.16	Received during 2016-17	Redressed during 2016-17	Pending as on 31.03.17	0	1,193	1,193	0
Pending as on 01.04.16	Received during 2016-17	Redressed during 2016-17	Pending as on 31.03.17						
0	1,193	1,193	0						

2 Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

<p>a. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA): The design and implementation of BSBDA with requirement of zero balance has, to a large extent, addressed the social concern of financial exclusion of the hitherto unbanked/ under-banked populace. • Jubilee Plus Savings Account for Senior Citizens: Keeping in view the needs of the elderly members of the society, the Bank has designed a zero balance Savings Account for Senior Citizens wherein the facilities and features have been tailored to suit their requirements. • Super Shakti Savings Account for Women: With a view to encouraging savings and financial independence amongst women, the Bank has designed a special Savings Account for Women wherein the facilities and features have been tailored to meet their specific requirements. • Current Account (CA) for Start-up Enterprises: Mindful of the vital role played by Start-up enterprises in the growth of business ecosystem and keeping in view the constraints faced by such entities for maintaining high balances in their operating CA in the initial business set-up phase, the Bank has designed a special CA with no balance maintenance charges for such entities. • Skill Loan Scheme – Under Education Loan: IDBI Bank is offering an education loan scheme to inculcate the spirit of self-confidence among youth through self-employment and utilise their wisdom and experience gained through professional training and education. • Education Loan to Physically Challenged Persons under National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFD) Guidelines: IDBI Bank is offering an education loan scheme for physically disabled Indian citizens who are aspiring for higher studies in India and abroad. The scheme is to provide knowledge to the disabled persons to make them capable and self-dependent through proper training in the field of traditional occupations and entrepreneurship. • Energy Efficient Housing Refinance Scheme – Under Home Loan: Housing loans to individuals up to ₹ 50 lakh disbursed by Primary Lending Institutions (PLIs) for purchase of Energy Efficient new residential housing units in certified residential building projects in urban areas are covered under the Scheme.
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • IDBI Bunkar Mudra Yojana: The Bank launched a scheme especially for lending to the handloom weavers in seven clusters viz. Maheshwar (Madhya Pradesh), Shantipur (West Bengal), Bargarh (Odisha), Kanchipuram (Tamil Nadu), Saulkuchi (Assam), Varanasi (Uttar Pradesh) and Dharmavaram (Andhra Pradesh). The product is aimed at providing adequate and timely assistance to the weavers to enable them to meet their credit requirements, investment needs (term loan) as well as for working capital, in a flexible and cost-effective manner. The scheme is implemented in rural as well as urban areas of the seven specific clusters. Customers under the scheme having working capital limit up to ₹ 50,000 are being issued a Rupay Debit Card. • Krishi Unnati Financing to Farmers Producer Companies: More than three-fourths of the farmers of the country are Small & Marginal Farmers (SFMF) and are having fragmented holdings. They lack economy of scale, resulting in low level of mechanisation/ adoption of technology and hence less productivity and profitability. Farmer Producer Companies (FPCs) are encouraged to be formed for aggregation at the farm level for both inputs as well as outputs, basically to gain collective bargaining power for small farmers/ producers. IDBI Bank was one of the first banks to launch a specific product for FPCs, duly considering the constraints faced by them, by offering liberal terms for credit facilities. Formation and growth of Farmer Producer Organisations (FPOs)/ FPCs is seen as a major step in empowering the Small & Marginal Farmers of the country for profitable farming. • Upfront Finance against Carbon Credits Receivables: Providing upfront finance against the carbon credits receivables from the Clean Development Mechanism projects, which have been registered or are near to registration with Clean Development Mechanism Executive Board and are commissioned or are near to commissioning.
b.	<p>For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):</p> <ol style="list-style-type: none"> Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year? 	NA
c.	<p>Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?</p> <ol style="list-style-type: none"> If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so. 	NA

d.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?	NA
e.	If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	NA
f.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	NA

3 Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

a.	Please indicate the Total number of employees.	18,187	
b.	Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis.	467	
c.	Please indicate the Number of permanent women employees	5,155	
d.	Please indicate the Number of permanent employees with disabilities	350	
e.	Do you have an employee association that is recognized by management.	As per practice, the Bank has not given recognised union status to any of the unions/ associations.	
f.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	NA in view of 'e' above.	
g.	Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as at the end of the financial year.		
	Category	No. of complaints filed during 2016-17	No. of complaints pending as at end of 2016-17
i.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil
ii.	Sexual harassment	6	6*
iii.	Discriminatory employment	Nil	Nil
h.	What percentage of your under-mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?		
i.	Permanent Employees	66%	
ii.	Permanent Women Employees	68%	
iii.	Casual/ Temporary/ Contractual Employees	50%	
iv.	Employees with Disabilities	66%	

* Includes 2 (two) complaints pertaining to previous years.

4 Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised.

a.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	Yes
b.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?	Yes

<p>c. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>The Bank is fully compliant with the extant reservation policy of the Government of India. The Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Managers and Deputy General Managers, for Scheduled Castes (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Persons With Disabilities (PWD) and Other Backward Classes (OBC) employees, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. The Bank maintains separate rosters for PWDs, as per the Government of India guidelines.</p> <p>The Bank undertakes several financial inclusion initiatives for the unbanked/ under-banked population of the country such as conducting financial literacy camps, opening rural financial inclusion branches in unbanked rural locations, opening accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc.</p> <p>While the Bank is committed to providing excellent service to all customers, it also ensures that the grievances of special customers like differently abled customers, senior citizens, persons who are not literate and pensioners are dealt with on priority.</p> <p>Further, in line with its CSR policy, the Bank funds eligible projects to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of the society and make a sustained positive contribution to the welfare of society at large.</p>
---	---

5 Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

<p>a. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?</p>	<p>The Bank's various policies protecting the human rights, directly or indirectly, cover only operations of the Bank and do not extend to its subsidiaries, suppliers, contractors, NGOs etc.</p> <p>The Bank follows all applicable guidelines on human rights.</p> <p>Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH): The Bank has in place an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Bank has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment. With an objective of creating awareness about the POSH among the employees, an interactive e-learning module has been hosted on the Bank's Learning Management System (OJAS) and one-day workshop on POSH had been conducted.</p>
---	--

		<p>Redressal of Complaints: The Bank acknowledges that customers are the core constituent of the Bank and their rights should be protected. To this end, the Bank has formulated ‘Customer Care Policy’, ‘Grievance Redressal Policy’, ‘Customer Severance Policy’, ‘Compensation Policy’, ‘Customer Rights Policy’ and also has a ‘Citizens Charter’ in place. Further, the Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Bank’s Commitment to Customers and Code of Bank’s Commitment to Micro and Small Enterprises.</p>
b.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	<p>Six complaints were filed regarding Sexual Harassment during 2016-17. Out of these, two complaints were satisfactorily resolved.</p> <p>For other stakeholder complaints, please refer response to point no. 2 under Principle 1.</p>

6 Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

a.	Does the policy relating to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	<p>The Policy covers IDBI Bank only.</p> <p>The Bank respects, protects and makes efforts to restore the environment by implementing measures like E-Waste Management, use of paperless eco-friendly technology, conservation of energy, etc. The Bank is also following the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, effective from May 01, 2012, issued by Ministry of Environment and Forests, Government of India.</p>
b.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Yes/ No. If yes, please give hyperlink for webpage etc.	<p>Yes. IDBI Bank in its endeavour to address environmental issues has assisted organisations to provide clean energy options in the form of solar powered systems and innovative programmes in various parts of the country.</p>

		<p>Details of CSR activities undertaken in 2016-17 with an aim to ensure environmental stability are as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Name of the activity/ organisation</th> <th>Purpose</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>The Energy and Resources Institute (TERI)</td> <td>Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' programme wherein 5,000 households across more than 100 villages in UP, Odisha, Bihar and Jharkhand are provided with solar lighting systems</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Madras School of Economics (MSE)</td> <td>Financial support to install solar power system at 'Centre of Excellence' in MSE's campus</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences</td> <td>Financial support towards installation of roof-top solar power panel at its Secunderabad campus</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dilasa Sanstha</td> <td>Financial support for executing 4th watershed development programme in Sonurli and Walnagar villages of Ralegaon block of Yavatmal district, Maharashtra.</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose	1.	The Energy and Resources Institute (TERI)	Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' programme wherein 5,000 households across more than 100 villages in UP, Odisha, Bihar and Jharkhand are provided with solar lighting systems	2.	Madras School of Economics (MSE)	Financial support to install solar power system at 'Centre of Excellence' in MSE's campus	3.	Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences	Financial support towards installation of roof-top solar power panel at its Secunderabad campus	4.	Dilasa Sanstha	Financial support for executing 4 th watershed development programme in Sonurli and Walnagar villages of Ralegaon block of Yavatmal district, Maharashtra.
Sr. No.	Name of the activity/ organisation	Purpose															
1.	The Energy and Resources Institute (TERI)	Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' programme wherein 5,000 households across more than 100 villages in UP, Odisha, Bihar and Jharkhand are provided with solar lighting systems															
2.	Madras School of Economics (MSE)	Financial support to install solar power system at 'Centre of Excellence' in MSE's campus															
3.	Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences	Financial support towards installation of roof-top solar power panel at its Secunderabad campus															
4.	Dilasa Sanstha	Financial support for executing 4 th watershed development programme in Sonurli and Walnagar villages of Ralegaon block of Yavatmal district, Maharashtra.															
c.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Yes/ No	Yes. The environmental risk assessment forms an integral part of Bank's Credit Appraisal system. Existing credit risk monitoring policy broadly ensures that all assisted clients continue to comply with the regulatory guidelines relating to sustainable environmental protection and pollution control by stipulating suitable conditions in the sanction letter.															
d.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?	IDBI Bank was the first public sector bank to establish an exclusive Cell working on Clean Development Mechanism. The Bank's carbon credit services included technical consultancy for assessment, Funding, Registration of Clean Development Mechanism projects, commercial advisory for sale of carbon credits etc. The Bank introduced an innovative product 'Upfront Finance against Carbon Credits Receivables' for extending financial assistance to corporates against projected carbon credit receivables. The product will be modified as per the new guidelines under Conference of Parties (COP) - 21.															

<p>e. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Yes/No. If yes, please give hyperlink for web page etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In line with the Bank’s Mission statement “relentlessly striving to become a greener Bank,” the Bank has taken initiatives for funding potential green projects based on clean technologies viz. wind and solar. IDBI Bank has sanctioned about 12 solar power projects. • The Bank assesses potential environmental risks that may arise on disposal of obsolete IT equipment and therefore the Bank has documented and implemented a Board-approved E-Waste Management Policy and has appointed vendors for safe disposal of obsolete IT equipment. • The Bank has automated many of its business processes. Further, the Bank is conducting paperless meetings etc. to reduce consumption of paper. • Wherever feasible, the Bank is using electronic media in place of paper-based media for communicating internally (approvals, circulars etc.), externally with the customers (monthly statement of accounts, e-mailers etc.), shareholders (annual reports), business partners, regulators and governments etc. • The Bank has directed all its branches/ offices to make payments to borrowers, vendors, etc./ disbursement of loans through credit to the account/ RTGS/ NEFT only, to save paper consumption. • The Bank has automated most of its staff-related functions including payment of salary, benefits, claims, attendance marking, performance appraisal, etc. thereby reducing paper consumption. • Server Virtualization: To reduce the server footprints in the data centres, the Bank has implemented a Server Virtualization mechanism through which number of individual physical servers has been reduced considerably by moving the applications in virtualized environment. This has resulted in less consumption of power and reduced heat transmission. <p>The following initiatives have been taken in the recent past for reduction in use of power and water :</p> <p>At Corporate Centre, Mumbai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisation of lifts with energy efficient Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive, microprocessor controlled systems to reduce power consumption • Replacement of old Chiller Pumps (8 x 75 HP) for central AC plant currently in process • Replacement of conventional lights with T-5/ LED lights • Sewage Treatment Plant (STP) operated for reuse of treated water for cooling towers make up water.
---	--

		<ul style="list-style-type: none"> Sensor-based wash basin and urinal water flows for water conservation <p>At the Bank's Bandra-Kurla Complex (BKC) Office building :</p> <ul style="list-style-type: none"> Solar panels have been installed for 30 KW power generation to cater to common lighting requirement. Light Emitting Diode (LED) light fittings and occupant sensors have been used. Energy efficient screw chillers have been used for air-conditioning. Sensor-driven water taps and dual flush systems have been installed in toilets to save water. Rain water harvesting done to collect rain water, which would help in ground water level. <p>At Jawaharlal Nehru Institute of Banking & Finance (JNIBF), Hyderabad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solar water heaters have been installed at the Bank's training institute JNIBF, Hyderabad <p>In addition to the above, the Bank is adopting water and energy conservation measures in all its new projects and renovation of existing premises.</p>
f.	Are the Emissions/ Waste generated by the company within the permissible limits given by Central Pollution Control Board (CPCB)/ State Pollution Control Board (SPCB) for the financial year being reported?	Being in the services sector, the Bank's operations generate very minimal emissions/ waste.
g.	Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at the end of Financial Year.	Nil
7 Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner		
a.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with: (Up to 3)	<p>Yes.</p> <p>Some of the institutions/ associations where IDBI Bank is a member are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Indian Banks Association (IBA) The Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) Indian Institute of Bank Management (IIBM) National Institute of Bank Management (NIBM)
b.	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	The Bank, being one of the largest banks, has always been engaging with the regulators and policymakers and industry bodies such as IBA, in a responsible manner for improvement in the areas of banking sector reforms, financial inclusion etc.

8 Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

<p>a. Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.</p>	<p>The Bank has embarked upon the path of financial inclusion of the unbanked/ under-banked population of the country in terms of the mission of the Government of India and the RBI. Towards this goal, the following initiatives have been taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • More than 300 unbanked Sub Service Areas (SSAs) (consisting of about 1200 villages) have been provided with basic banking services through the Information and Communications Technology (ICT) enabled Business Correspondent Model. • The Bank has opened 253 rural financial inclusion branches in unbanked rural locations with an aim to augment its rural outreach. • More than 11 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs) have been opened in the country under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) scheme, having deposit balance of ₹ 225 crore (average balance ₹ 1,910). • Financial literacy is an integral part of financial inclusion. The Bank’s rural branches conduct outdoor financial literacy camps in their service area. During 2016-17, about 490 camps have been held which were attended by about 8,800 villagers. The Bank also conducts street plays in rural areas, educating the people about financial products. More than 250 such plays have been conducted. Besides, more than 170 financial literacy camps were also organised for students at schools in Gujarat/ Madhya Pradesh/ Maharashtra. • The Bank has conducted Kisan Sangosthis at around 660 places across the country. About 30,000 farmers participated in Kisan Sangosthis. Information relating to digital banking and cashless transactions was imparted to the farmers in Kisan Sangosthis. • Micro loans of more than ₹ 1,700 crore provided under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) for more than 1.5 lakh account holders to give a boost to flow of credit to micro industry. <p>Besides undertaking several financial inclusion initiatives, the Bank, through its CSR initiatives, also contributes towards sustainable and holistic development through various programmes having multi-dimensional impact. Towards this end, during 2016-17, the Bank undertook a number of CSR activities aimed at providing improved access to health services, promoting education for children, promoting gender equality, enhancement of livelihood opportunities and advancement of vocational and employable skills.</p>
--	--

<p>b. Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/ own foundation/ external NGO/ government structures/ any other organization?</p>	<p>The programmes are undertaken by in-house teams with the help of outsourced agencies, particularly for provision of technology and personnel manning the Business Correspondent (BC) outlets.</p> <p>CSR programmes relating to inclusive growth and equitable development are largely undertaken through NGOs and government organisations and to a certain extent through the Bank's branches.</p>
<p>c. Have you done any impact assessment of your initiative?</p>	<p>Impact assessment of CSR initiatives is carried out by the implementing partner. Besides, under the financial inclusion initiatives of the Bank, the impact assessment is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. The micro insurance schemes and the pension scheme have helped the Bank and the Government of India in formally inducting the deprived people into the financial mainstream. <ul style="list-style-type: none"> - More than 10 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). - More than 5 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY). - More than 0.50 lakh bank accounts holders have been enrolled under Atal Pension Yojana (APY). ii. 44.03 lakh accounts out of a total of 112 lakh active saving banks (SB) accounts (39.3%) and 4.29 lakh accounts out of total 7.86 lakh active Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts (54.6%) are linked with Aadhaar, thus paving the way for Government of India's resolve to distribute subsidies and benefits directly into bank accounts through Aadhaar, to plug leakages and pilferages. iii. As on March 31, 2017, the Bank had opened more than 30 lakh basic SB accounts, i.e. accounts opened with zero balance under financial inclusion initiatives of the Bank. iv. The Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) in Satara district in Maharashtra conducts free residential job-oriented training programmes for the rural unemployed youth to empower them to be self-employed. Since inception, RSETI has trained 3,657 candidates.

<p>d. What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.</p>	<p>Details of the community development projects of the Bank, undertaken in collaboration with reputed organisations, are given below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Name of the activity/ organization</th> <th>Purpose</th> <th>Expenditure incurred during 2016-17 (₹ lakh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi</td> <td>Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' programme wherein 5000 households in select villages across four states are provided solar lighting systems.</td> <td>32.02</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Habitat for Humanity India Trust</td> <td>Financial support to provide water wheels to rural women for facilitating ease in carrying water in Nanded and Osmanabad districts of Maharashtra.</td> <td>11.75</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>CSR Activities in Varanasi and Chandauli Districts of Uttar Pradesh</td> <td>Adoption of two villages - Suzabad in Varanasi district and Bhabhaura in Chandauli district for undertaking various CSR activities viz. construction of roads, community hall, provision of solar light lamp posts, toilets and submersible water pumps, and refurbishment of school building.</td> <td>70.49</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Rashtriya Gramin Vikas Nidhi</td> <td>Development of Model Village in Morigaon district, Assam.</td> <td>3.76</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Name of the activity/ organization	Purpose	Expenditure incurred during 2016-17 (₹ lakh)	1.	The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi	Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' programme wherein 5000 households in select villages across four states are provided solar lighting systems.	32.02	2.	Habitat for Humanity India Trust	Financial support to provide water wheels to rural women for facilitating ease in carrying water in Nanded and Osmanabad districts of Maharashtra.	11.75	3.	CSR Activities in Varanasi and Chandauli Districts of Uttar Pradesh	Adoption of two villages - Suzabad in Varanasi district and Bhabhaura in Chandauli district for undertaking various CSR activities viz. construction of roads, community hall, provision of solar light lamp posts, toilets and submersible water pumps, and refurbishment of school building.	70.49	4.	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi	Development of Model Village in Morigaon district, Assam.	3.76
Sr. No.	Name of the activity/ organization	Purpose	Expenditure incurred during 2016-17 (₹ lakh)																		
1.	The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi	Financial support to TERI's 'Lighting a Billion Lives' programme wherein 5000 households in select villages across four states are provided solar lighting systems.	32.02																		
2.	Habitat for Humanity India Trust	Financial support to provide water wheels to rural women for facilitating ease in carrying water in Nanded and Osmanabad districts of Maharashtra.	11.75																		
3.	CSR Activities in Varanasi and Chandauli Districts of Uttar Pradesh	Adoption of two villages - Suzabad in Varanasi district and Bhabhaura in Chandauli district for undertaking various CSR activities viz. construction of roads, community hall, provision of solar light lamp posts, toilets and submersible water pumps, and refurbishment of school building.	70.49																		
4.	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi	Development of Model Village in Morigaon district, Assam.	3.76																		
<p>e. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.</p>	<p>CSR projects aimed at community development are designed in consultation with all relevant stakeholders, including the local populace and ground-level beneficiaries. As such, involvement of the community is ensured at the beginning and the participation of community in various steps of implementation of the project ensures that the initiative is successfully adopted by the community.</p>																				

9 Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

a.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as at the end of the financial year.	Out of the total complaints handled, about 1% i.e. 622 complaints were pending as on March 31, 2017.
b.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/ N.A./ Remarks (additional information)	NA
c.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as at the end of the financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Nil
d.	Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	The Bank captures customer feedback on an on-going basis. The Bank also obtains customer feedback on quality of service at branches through Branch Level Customer Service Committee (BLCSC) meetings held every month at which customers from various sections of the society are invited. The customers' insights are used towards improvement of processes to delight customers. Further, on the basis of the Annual Survey of Bank Branches conducted by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), the Bank has been given a high rating on the parameter of Customer Feedback.